eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू राजनीति में भारत की एक्ट ईस्ट नीति अवसर चुनौतियां एवं सामरिक निहत्तार्थ

डॉ0 नलिनी लता सचान[1]
[1]सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान, डी.ए.वी कॉलेज, कानपुर, उ0प्र0

Received: 21 July 2026 Accepted & Reviewed: 25 July 2026, Published: 31 July 2026

Abstract

21वीं सी सदी की बदलती वैश्विक व्यवस्था में शक्ति राजनीति का केंद्र अमेरिका तथा यूरोप से स्थानांतरित होकर एशिया और हिन्द–प्रशांत क्षेत्र होता जा रहा है। इस क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व केवल आर्थिक न होकर सामरिक राजनीतिक एवं सामुद्रिक क्षेत्र तक विस्तृत है। जिससे यह क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र के महत्व तथा अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का ध्यान में रखकर भारत ने अपनी पूर्ववर्ती लुक ईस्ट पॉलिसी को सन 2014 में और अधिक सक्रीय स्वरूप प्रदान करते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विकास के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक ,राजनीतिक सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को पहले से अधिक सुदृढ़ और मजबूत करना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक नियम आधारित समावेशी, स्मृति तथा वैश्विक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा मुक्त क्षेत्र बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू–राजनीति के दृष्टिगत भारत की एक्ट ईस्ट नीति की समीक्षा करता है तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा इससे जुड़े विभिन्न संगठनों जैसे आसियान, बिम्सटेक, क्वॉड तथा हिन्द प्रशान्त पर आसियान दृष्टिकोण (AOIP) सुदृढ़ के साथ उसके सुदन होते संबंधों को रेखांकित करने के साथ ही लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द– एक्ट ईस्ट नीति, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद प्रशांत, आसियान ,क्वॉड, बिम्सटेक, भू–राजनीति, दक्षिण पूर्व, भारत।

Introduction

अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। भारत और इस क्षेत्र के मध्य व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद भारत में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई किंतु 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति तथा भारत द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई जाने के बाद भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को और प्रगाण करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने लुक ईस्ट नीति प्रारंभ की[1]। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्विधुवीय भी विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई बदली हुई शक्ति संरचना, आर्थिक वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति समुद्री मार्गों का विस्तार तथा बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा उसके समुद्री क्षेत्र जैसे मलक्का जलडमक मध्य, दक्षिण

[1] (जे. एन. दीक्षित, भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिकहाउस, 2013, पृष्ठ –15–21) जिसका उद्देश्य आसियान देश के साथ व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

चीन सागर तथा हिन्द प्रशांत महासागर क्षेत्र को न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है।[2] दक्षिण पूर्व एशिया के बढ़ते हुए महत्व ने इस क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ने केन्द्र भी बना दिया है। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न हो रहे विवाद, हिन्द प्रशांत क्षेत्र का सामरिक व रणनीतिक महत्व, आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुर्नगठन क्षेत्रीय संगठनों की बदलती भूमिका तथा समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता ने भारत के समक्ष नई चुनौतियां एवं अवसर के अनुरूप अधिक सक्रिय विदेश नीति की आवश्यकता उत्पन्न की। परिणामस्वरूप सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आयोजित ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में अपनी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में परिवर्तित करने की घोषणा की।[3] यद्यपि इस नीति को अपनाकर भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को नई गति प्रदान की है किंतु इस नीति के वास्तविक प्रभाव, उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर व्यापक विमर्श आवश्यक है। में एक प्रयास है। जो भारत की विदेश नीति, हिंद प्रशांत रणनीति तथा दक्षिण पूर्व एशिया की समकालीन भू–राजनीति को समझने में उपयोगी होगा।

लुक ईस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति तक विकास, परिवर्तन और समकालीन प्रासंगिकता सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लुक ईस्ट नीति की घोषणा की थी। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में नये परिवर्तन जोड़ते हुये पूर्वी एशिया के उभरते बाजारों के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।[4] इस क्रम में पहले भारत आसियान का संवाद साझेदार बना। संवाद में 1996 में पूर्ण संवाद साझेदार का दर्जा प्राप्त कर लिया। सन 1991 से 2002 के मध्य तक भारत और आसियान के मध्य व्यापार निवेश तथा तकनीकी सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तत्पश्चात भारत ने अपनी दक्षिण–पूर्व एशिया विदेश नीति को और विस्तार प्रदान करते हुये आर्थिक सहयोग से बढ़कर रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा तथा क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग पर भी बल देना प्रारम्भ कर दिया। इस दौरान भारत–जापान, भारत–दक्षिण कोरिया तथा भारत–वियतनाम सम्बन्धों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।[5]

सन 2002 के पश्चात से भारत नियमित रूप से आसियान शिखर सम्मेलनों में भाग लेने लगा तथा 2012 में भारत–आसियान संबंधों को स्त्रातजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त हुआ।[6] लुक ईस्ट नीति के तहत भारत ने पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने हेतु अनेक संपर्क परियोजनायें भी प्रारम्भ की। जिसमें भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान परियोजना शामिल है।

[2] अमिताभ आचार्य, द मेकिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंटरनेशनल रिलायंस ऑफ अ रीजन, सिंगापुर, ISEAS पब्लिशिनी, 2013 Pg- 245—252)

[3] (विदेश मंत्रालय भारत सरकार, Act East Policy – नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय 2014)

[4] (सी. राजा मोहन –Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy] Penguin Books India- 2003 Pg-173)

[5] (David Scott "India's Look East Policy: Shifting Strategic Perspectives" Contemporary Southeast Asia & Vol- 29] No- 1 2007 - Pg- 123-145)

[6] S.D. Mani Two Decades of India's Look East Policy नई दिल्ली, मनोहर पब्लिशर्स – 2012, Pg – 45–58)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

दक्षिण–पूर्व एशिया तथा हिन्द–प्रशांत क्षेत्र के लगातार बढ़तें हुए वैश्विक महत्व के दृष्टिगत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लुक ईस्ट नीति को और अधिक सक्रियता प्रदान करते हुए 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो कि म्यांकार के नेपीड़ा में आयोजित हुआ था लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित करने की घोषणा की। इस नीति के तहत आर्थिक सहयोग के साथ–साथ सामरिक सुरक्षा तथा इन्डो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया।[7] इस नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करना ही नही है बल्कि भारत को हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में एक उत्तरदायी व विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करना भी है। इसके लिये आर्थिक क्षेत्र में भारत और आसियान के मध्य व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने के प्रयत्न किये गये साथ ही वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, फिनटेक तथा हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार का प्रयत्न किया गया है।[8] सहयोग को और अधिक विस्तार देने के लिये सम्पर्क परियोजनायें जो एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है। को पूर्ण करने पर बल दिया जा रहा है। भारत–म्यांमार–थाईलैंड राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाना है। 1600 किमी0 लम्बी यह परियोजना क्षेत्रीय व्यापार परिवहन, निवेश, पर्यटन तथा सास्कृतिक सम्पर्क को दबा दने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इस प्रकार का लाइन मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ने का प्रयास करती है।[9] सितवे से पलेटवा तक कलादान नदी के माध्यम से अन्तर्देशीय जलमार्ग बनाया गया है। यह परियोजना सड़क, नदी तथा समुद्र तीनों का उपयोग करती है इसलिये इसे मल्टी–मॉडल परियोजना कहा जाता है। ये परियोजनायें पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के साथ ही चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को सन्तुलित करने के दृष्टि से सामरिक महत्व की भी हैं।

भारत ने दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इण्डोनेशिया व वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिये नौसैनिक अभ्यास, तटरक्षक सहयोग तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को लगातार बढ़ाया है। भारत सदैव हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन का समर्थक रहा है।[10]

दक्षिण–पूर्व एशिया की बदलती भू–राजनीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण–पूर्व एशिया में आसियान के 10 देश सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इण्डोनेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैण्ड तथा क्रुनेई शामिल हैं। हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाले जलमार्ग के केन्द्र में स्थित होने के कारण इक्कसवीं सदी में यह क्षेत्र विश्व राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक क्षेत्र बन गया है। मलक्का जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर तथा सिंगापुर जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गो से विश्व

[7] Shyam Sharan & How India Sees the World Juggernaut Books- 2017 PP 92-46
[8] ASEAN Secretariate] ASEAN&India Trade and Investment Report -Jakarta 2024 |
[9] S.M. Mani India's Eastward Engagement: From Antiquity to Act East Policy - Sage Publication New Delhi - 2019. Pg - 214-223A
[10] (सी. राजा मोहन – Samudra Manthan: Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific - Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace 2012, Pg-101-118

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

व्यापार का एक बड़ा भाग संचालित होता है।[11] जिस कारण यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, निवेश तथा हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा समुद्री मार्गों के लिये आवश्यक है। इस क्षेत्र में विश्व शक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। भारत की Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2019 में की थी हिन्द–प्रशांत क्षेत्र को एक मुक्त, समावेशी, नियम आधारित, सुरक्षित तथा समृद्ध समुद्री व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी, सागर SAGAR Security and Growth for all in the region तथा हिन्द–प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख आधार है। इसके साथ ही यह पहल भारत और आसियान देशों के मध्य समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। इसके माध्यम से भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इण्डोनेशिया, सिंगापुर तथा अन्य हिन्द–प्रशांत साझेदारों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाया है।

बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिण–पूर्व एशिया में क्वाड (Quad) तथा AUKUS जैसे मंचों का महत्व भी बढ़ा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य है और इस संगठन का उद्देश्य हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में स्वतन्त्र, समावेशी तथा नियम आधारित व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना है। यद्यपि भारत आकुस का सदस्य नहीं है लेकिन यह संगठन भी हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की सामरिक राजनीति पर अपना प्रभाव डाल रहा है। समकालीन आसियान देशों की बढ़ती क्षमता से यह क्षेत्र वैश्विक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि, ऑटोमोबाइल तथा डिजिटल उद्योगों का केन्द्र बन चुका है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षिण–पूर्व एशिया में खोज की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपूर्ति श्रृंखला को भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) के माध्यम से और अधिक विविध और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है।

एक्ट ईस्ट नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का भी परिचायक है। अमेरिका, यूरोप, रूस के साथ संबंधों के साथ ही भारत आसियान तथा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी सहयोगात्मक संबंध बनाये रखता है तथा साथ ही हिन्द–प्रशांत क्षेत्र को महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बनने की बजाय स्वतन्त्र, उत्तरदायी तथा नियम आधारित क्षेत्र बनाये रखने की नीति का समर्थक है। गत कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का दखल बढ़ा है जो कि भारत के लिये चिन्ता का विषय है। BRI के माध्यम से चीन ने अनेक देशों में आधारभूत संरचनाओं में व्यापक निवेश किया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, सैन्य ढांचे का विस्तार तथा व्यापक समुद्री दावों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दिया है। अनेक दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के समुद्री विवाद अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय हैं।[12] भारत का दृष्टिकोण इस विषय पर किसी भी विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन तथा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के पालन का समर्थन करना रहा है ताकि निर्बाध वैश्विक व्यापार का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

भारत और आसियान के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों के साथ ही रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबन्धन,

[11] Amitav Acharya 'The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region Singapore: ISEAS Publishing 2013 Page 41-58.
[12] United Nations] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

सम्पर्क परियोजनायें जैसे अनेक क्षेत्रों में निरन्तर सहयोग बढ़ रहा है। ASEAN & India Free Trade Agreement (AIFTA) ने द्विपक्षीय व्यापार को गति प्रदान की है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में BIMSTEC और मेकांग–गंगा सहयोग परियोजना का भी विशेष महत्व है। BIMSTEC बंगाल की खाड़ी से जुड़े सात देशों– बांग्लादेश, भूटान, इण्डिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाइलैण्ड का क्षेत्रीय संगठन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार तथा थाइलैण्ड के माध्यम से आसियान देशों से जोड़ने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्ट ईस्ट पालिसी में भारत इस मचं के माध्यम से बहुआयामी सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहा है। मेंकांग गंगा सहयोग की स्थापना नवम्बर– 2000 में की गई थी। इस सहयोग का आधार भारत की गंगा नदी तथा दक्षिण पूर्व एशिया की भेकांग नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर रखा गया है। इसके सदस्य इण्डिया, थाइलैण्ड, म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस तथा वियतनाम।[13] यह एक्ट ईस्ट पालिसी का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तम्भ है। भारत यह आशियान सम्बन्ध एक्ट ईस्ट नीति की आधार शिला है। आर्थिक सहयोग के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों में हुई प्रगति लुक ईस्टनी ईस्ट नीति की प्रमुख उपलब्धियॉ है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति यद्यपि भारत की एक बहुउददेशीय विदेश नीति है किसी अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां है. लेकिन साथ ही इस नीति के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के समक्ष भव भी अनेक चुनौतियॉ है। भारत म्यांमार सीमा पर राजनीतिक अस्थिरता, गृह–युद्ध तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के कारण कलादान परियोजना तथा भारत–म्यांमार थाईलैण्ड ट्राइलेटरल हाईवे जैसी परियोजना अभी भी अपूर्ण है। म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता के कारण पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने की योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न हुई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता निवेश क्षेत्रीय रणनीति उपस्थिति तथा आसियान देशो में चीन का प्रभाव भारत के लिये एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा दक्षिण चीन सागर विवाद और क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन की राजनीति भारत की सन्तुलित विदेश नीति के समक्ष चुनौतियॉ उत्पन्न करती है। पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी अवसंरचना की कमी तथा भारत म्यामार सीमा पर उग्रवाद, मादक पदार्थो की तस्करी तथा हथियारों की आवाजाही जैसी समस्याओं कारण एक्ट ईस्ट नीति के लाभों का पूर्ण उपयोग से नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त आसियान के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा, सीमित संसाधन तथा आसियान देशों की स्वयं की भिन्न आर्थिक व राजनीतिक प्राथमिकतायें भारत के समाप्त दीर्घ कालीन चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिये आवश्यक है कि भारत सम्पर्क परियोजनाओ को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के प्रयत्न करें साथ ही पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं सड़क, रेल, बन्दरगाह तथा डिजिटल अवसरंचना का विकास करे जिससे आसियान देशों के साथ सम्बन्ध को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही आसियान के साथ सहयोग के नये क्षेत्र जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी तथा आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार किया जाना चाहिये। समुद्री क्षेत्र मे भी सहयोग के लिये नये क्षेत्र खोजकर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सम्बन्धों को मजबूत नाने के प्रयास आवश्यक है।

निष्कर्ष– भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक बहुआयामी विदेश नीति है। जिसका लक्ष्य दक्षिण–पूर्व एशिया तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करना

[13] Mekong Ganga Cooperation, Vientiance Declaration - 2000

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 07, July 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.21744507

है। एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के साथ ही भारत की क्षेत्रीय तथा वैश्विक भूमिका को मजबूती प्रदान की है।यद्यपि अभी भी भारत के समक्ष अनेक क्षेत्रीय समस्यायें विद्यमान है फिर भी प्रभावी क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से यह भारत के दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रहेगी।

सन्दर्भ सूची

1. दीक्षित जे0एन0 (2003), भारत की विदेश नीति , नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस।

2. सिकरी, राजीव (2012) चुनौती और रणनीति : भारत की विदेशी नीति पर पुनर्विचार, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स।

3. शर्मा, हरिशचन्द्र, भारत की विदेश नीति, जयपुर, कालेज, बुकडिपों।

4. सिंह लल्लन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं भारत की विदेश नीति, इलाहाबाद किताब महल।

5. आचार्य ए. (2013) द मेकिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन्टरनेशनल रिलेशन्स ऑफ ए रीजन, सिंगापुर, आई.एस.ई.ए.एस. पब्लिशिंग।

6. मोहन, सी. राजा (2012) समुद्र मन्थन, साइनो : इण्डियन राइवलरी इन द इन्डो पैसिफिक, वाशिंगटन डी0सी. कार्नेगो इन्डोवमेन्ट फार इन्टरनेशनल पीस।

7. मुनि एस.डी. (2012) टू डिकेडस आफ इण्डियास लुक ईस्टपॉलिसी, नई दिल्ली, मनोहर पब्लिकेशन्स।

8. मुनि, एस.डी. (2019) इण्डियाज ईस्टवार्ड इन्गेजमेन्टः फ्राम टन्टीम्यूटी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स।

9. आसियान सेक्रेटरीएट (2019) आसियान –आउटलुक ऑन द इन्डो पैसेफिक जकार्ता आसियान सेक्रेटरीएट।

10. आसियान सेक्रेटरीएट (2024) आसियान –इण्डिया डायलाग रिलेशन्स, जकार्ता आसियान सेक्रेटरीएट।

11. आसियान सेक्रेटरीएट (2024) आसियान –ईयरबुक 2024, जकाकर्ता आसियान सेक्रेटरीएट।

12. गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयरर्स (2019) इन्डो पैसिफिक, ओशन इनीशिएटिव नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।

13. गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (2025) एनुअल रिपोर्ट 2024–25 नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।

14. गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (2024) आसियान इण्डिया ट्रेड स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली।

15. रिसर्च एण्ड इन्फोरमेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कन्ट्रीज (RIS) (2023) सप्लाई चेन रिजिलिएन्स इनिशिऐटिव, नई दिल्ली।